

trained personnel but it is for the State Governments to send their personnel for training.

Shri A. M. Thomas : In view of our big multi-purpose projects, has any scheme been prepared by the Health Ministry in co-ordination with the Ministry of Irrigation and Power for the supply of drinking water?

Shrimati Chandrasekhar : There is no such scheme.

Shri Hem Raj : May I know whether, in the backward hilly areas where the people are very poor, they will be given some subsidy instead of loans?

Shrimati Chandrasekhar : I said so in my reply. According to the schemes that we receive from the State Governments, we grant money; for the rural areas it is grant-in-aid and for urban areas, it is loan. It is for the State Governments to formulate schemes and decide things.

Shri G. P. Sinha : What amount of loan or subsidy has been given to Bihar, especially in view of the drought this year in Chhota Nagpur?

Shrimati Chandrasekhar : For Bihar, up to the end of 1955, the amount of loan is Rs. 100 lakhs.

ज्योतिर्मठ-बद्रीनाथ रोड

*८६१. श्री भक्त बर्शन : क्या परिवहन मंत्री ५ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ तक मोटर के लिये सड़क बनाने के बारे में तब से क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सहासचिव (श्री शाहनवाज खाँ) : इस सड़क के बनाने का सम्बन्ध मुख्य तौर पर (Primarily) उत्तर प्रदेश सरकार से है और वह अभी तक इस मामले पर विचार कर रही है।

श्री भक्त बर्शन : क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष जब माननीय उप मंत्री महोदय ने बद्रीनाथ की यात्रा की थी तो स्वयं उन्होंने इस

सड़क की आवश्यकता को अनुभव किया था, और क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा जा रहा है कि जल्दी की जाय ?

श्री शाहनवाज खाँ : जी हाँ उत्तर प्रदेश की सरकार को कई दफा लिखा गया है। आखिरी बार जुलाई १९५५ में लिखा गया था और उन का जवाब सितम्बर १९५५ में आया था।

श्री भक्त बर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि पिछले दस वर्षों में इस सड़क में केवल दस मील कि बढातरी हुई है और चूँकि यह अखिल भारतीय महत्व की सड़क है क्या इस के लिये विशेष अनुदान देने कि आवश्यकता अनुभव की जा रही है

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम इस सड़क को काफी जरूरी समझते हैं और जैसा आप ने कहा कि डिप्टी मिनिस्टर साहब उधर गये थे और वहाँ उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था लेकिन इस सड़क को जल्दी बनाना उत्तर प्रदेश की सरकार पर निर्भर करता है जो मदद हम देना चाहते हैं उस में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री गोविंददास : इस सड़क के बनाने में कितना रुपया खर्च होगा और बद्रीनाथ मंदिर के एक अखिल भारतीय संस्था होने के कारण उस में से कितना रुपया केंद्रीय सरकार देने को तैयार है ?

श्री शाहनवाज खाँ : अभी तक जो प्रोग्राम था जोशी मठ तक सड़क बनाने का, उस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ३३ लाख ७४ हजार रुपये देने का वादा किया था और जो प्रांतीय सरकार है उस को उस में से निस्फ देना था। आगे का जो हिस्सा बद्रीनाथ तक का है उसके लिये एस्टिमेट्स माँगे गये हैं, जब वह आ जायेंगे तब फिर कोई फंसला किया जायेगा।

गन्ना ढोने के लिये माल डिब्बोंका बिया जाना

*८६२ श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में विभिन्न रेलवे स्टेशनों-से गन्ना ढोने के लिये रेलवे से छोटी लाइन और बडी लाइन के कितने डिब्बे माँगे गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे ने अपेक्षित संख्या में माल डिब्बो को देने के बारे में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों का गन्ना चीनी मिलों तक समय पर पहुंचाने के लिये और कौन से उपायों को सोचा गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है [द्वितीय परिशिष्ट ५ अनुबंध सं ४०]

(ख) जी नहीं ।

(ग) गन्ना भेजने के लिए डिब्बों की प्रायः सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है । केवल उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों पर कुछ मांगें पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि उनका पूरा करना रेल-प्रशासनों के बश की बात नहीं थी ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है उस में कुल ५३,६६६ डब्बे बड़ी लाइन के लिये मांगे गये हैं, १३६,०५७ छोटी लाइन के लिये मांगे गये हैं और इन में से १०७,६२७ डब्बे पूर्वोत्तर रेलवे के लिये मांगे गये हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर सकती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बड़े बड़े स्टेशन हों जहाँ से गन्ना ज्यादा लादा जाता है उन पर सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी टुक चलाई जायें ताकि किसानों का गन्ना मिलों तक पहुंच जाय और सरकार को भी आमदानी हो ?

श्री शाहनवाज खाँ : अभी तक पूर्वोत्तर रेलवे के लिये रेलवे प्रशासन ने २,२५० डब्बे सिर्फ गन्ना ढोने के लिये रखे हैं और ३५ गन्ना घटल गाड़ियां भी चलती हैं । हमें कोई खास दिक्कत गन्ना हटाने के बारे में महसूस नहीं हुई है । जब कोई ऐसी दिक्कत महसूस होगी तो फिर शायद किसी दूसरी चीज पर गौर किया जाय, लेकिन अभी तक कोई खास दिक्कत महसूस ही नहीं हुई ।

श्री विभूति मिश्र : अभी पालियामेन्टी सेक्रेट्री साहब ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले जो बयान दिया उस में उन्होंने कहा था कि दिक्कत महसूस हुई है । मैं जानता हूँ कि इन दो बयानों में से किस पर विश्वास किया जाय ।

श्री शाहनवाज खाँ : बयान में मैंने कहा था कि केवल उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों पर कुछ

मांगें पूरी नहीं की जा सकीं । वह अभी तक पूरी नहीं हो सकीं पर हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस के हो जाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ।

Shri K. P. Tripathi : May I know whether it is a fact that great stress is felt in some parts of the North-Eastern Railway for lack of wagons so much so that the cost of living in certain areas had risen because goods cannot be moved? In these circumstances, may I know if the Ministry is giving priority to that area and in what period of time we are likely to get out of this difficulty?

The Minister of Railways and Transport (Shri L. B. Shastri) : May I give the figures of indents and loadings. As Shri Bibhuti Mishra just now pointed out, the indents were for 1,07,827 wagons and the wagons supplied were 1,02,434. The difference is very small. It is only about 5,000. This situation has arisen on account of various difficulties. I would not like to go into them. During the Budget discussions, I gave detailed informations. We were doubling certain lines. It is all due to line capacity. The wagon position will not be so difficult in the current year because we are getting enough number of metre gauge wagons. The line capacity work has to be considerably increased and it is being done on an extensive scale and within this year, it would be possible to carry many more wagons and perhaps many more trains, when the line capacity works are completed. I do not think there will be any special difficulty in regard to the movement of sugarcane. If other means of transport are required it is not the job of the railways. Private carriers can do that work or if any other agency wants to take it up, we have no objection.

Shri G. P. Sinha : May I know whether the shortage of wagons is entirely due to the increased production of steel?

Mr. Speaker : We are on sugarcane.

Shri G. P. Sinha : Is the shortage entirely due to the great projects for steel production?

Shri L. B. Shastri : There has been some difficulty about steel. Perhaps the hon. Member means to suggest that the manufacture of wagons and other things were held up on account of shortage of steel, but the position is now improving gradually and we hope that there will be no difficulty in the supply of steel, so far as the Railways are concerned.

AIR AGREEMENT WITH U. K.

*863. **Sardar Iqbal Singh :** Will the Minister of Communications be pleased to state when the bilateral Air Agreement between India and the United Kingdom is proposed to be reviewed?

The Minister in the Ministry of Communications (Shri Raj Bahadur) : It is proposed to hold the annual review for determining the frequencies of services etc. to be operated by the airlines designated by the respective Governments during the next 12 months, sometime in the middle of April, 1956.

Sardar Iqbal Singh : May I know whether it is a fact that the Government of United Kingdom is not agreeing to our increasing the frequency of service between India and England?

Shri Raj Bahadur : No, Sir. Our past experience has been that wherever we have met in such conferences we have been able to mutually settle and agree about the frequencies to be operated by the services of each of the two countries. We hope the same thing will happen in future.

Sardar Iqbal Singh : May I know whether the Government will have reservation of passengers, as they have done with other countries, with the United Kingdom also?

Shri Raj Bahadur : These questions come up at the time of the conference. I can only say that we wanted to increase our frequencies from 5 to 6 on the United Kingdom sector and they agreed to it last year.

CO-OPERATIVE TRAINING CENTRES

*865. **Shri Sivamurthi Swami :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 792 on the 13th December, 1955 and state:

(a) the number of candidates who have received training in the various Co-operative Training Centres so far; and

(b) the total expense incurred thereon?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh) : (a) 188 candidates have received higher training and 195 candidates have received intermediate training.

(b) Rs. 5.7 lakhs have been spent by the Reserve Bank of India from 1-6-54 to 31-1-56 on account of training of higher and intermediate personnel.

Shri Sivamurthi Swami : May I know whether all these persons have received training in the country or abroad?

Dr. P. S. Deshmukh : They have all received training in the country.

Shri Velayudhan : May I know whether any co-operative training institute subsidised by the Reserve Bank, is operating in the Travancore-Cochin State, how many students were trained and whether all of them are employed or not after training?

Dr. P. S. Deshmukh : We do not go so much State-wise. I would require notice to find out whether Travancore-Cochin State has got one or not. So far as subordinate personnel are concerned, training of subordinate personnel is held in 13 States among which I find the name of Travancore-Cochin.

Shri Velayudhan : May I know whether it is a fact that in the training centres or co-operative training institutes many of the professors or lecturers employed are merely part-time employees of the local colleges and they have not got any other advanced training in co-operative movement or the technical side of it?